राष्ट्रीय

# सरकारी प्रचार : मोदी के सिखों से रिश्ते पर छपी किताब

**यूसुफ किरमानी**

भाजपा को ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के संबंध सिखों के साथ अटूट नहीं रहे। अब यह नौबत आ गई कि उसे बताने के लिए बुकलेट छापनी पड़ी है और विभिन्न मंत्रालयों के नेटवर्क के ज़रिए देशभर में बाँटा जा रहा है। तमाम लोगों को इसे ईबुक के रूप में भी ईमेल पर भेजा गया है।

कल तक भारतीय एजेंसियाँ इस कॉरिडोर का संबंध खालिस्तानी आतंकियों और पाकिस्तान वाले इलाक़े में आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाने की बातें मीडिया में सूत्रों के हवाले से कहलवाती रही हैं। आज सरकार को बताना पड़ रहा है कि सिखों से मोदी के अटूट संबंध हैं। यह बुकलेट शब्दों की चाशनी से भरी पड़ी है। 33 पेज की यह बुकलेट नुमा किताब हिन्दी, अंग्रेज़ी और गुरमुखी भाषाओं में है। इसका प्रकाशन सूचना प्रसारण मंत्रालय ने किया है। बुकलेट में करतारपुर साहिब कॉरिडोर का सारा श्रेय मोदी को दे दिया गया है। किताब को मोदी के सिख वेशभूषा वाले फोटो से पाट दिया गया है।

**हक़ीक़त तो ये है**

हालाँकि सिख समुदाय का बच्चा बच्चा जानता है कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू, कैप्टन अमरिंदर सिंह और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की कोशिशों की वजह से मुमकिन हो सका है।

इसकी कोशिशें वर्षों से चल रही थीं लेकिन अपनी पाकिस्तान यात्रा पर नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने क्रिकेटर दोस्त इमरान खान से इस कॉरिडोर का वादा लिया। 2018 में इमरान ने पाकिस्तान की सत्ता संभालते ही करतारपुर साहिब कॉरिडोर की पहली

कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।

इसके बाद इसमें मोदी सरकार कूदी और आधिकारिक स्तर पर बातचीत के दौर शुरू हो गए। 9 नवम्बर 2019 को प्रधानमंत्री मोदी सिखों वाली पगड़ी पहनकर भारत के हिस्से वाले कॉरिडोर का उद्घाटन करने जा पहुंचे। उसी कार्यक्रम में बतौर प्रधानमंत्री,, मोदी को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर ने क़ौमी एकता पुरस्कार से नवाज़ा।

बुकलेट में इस पुरस्कार का जो औचित्य कमेटी ने उस समय बताया था उसे ज्यों का त्यों पेश कर दिया गया हैं। हालाँकि उस समय हुए सरकारी समारोह में दिए गए इस पुरस्कार को सरकार के गोदी मीडिया ने ज़्यादा अहमियत नहीं दी थी। लेकिन अब तो मोदी की शान में उस समय पढ़े गए कसीदों को किसान आंदोलन का सामना करने के लिए भुनाया जा रहा है।

**बदनाम करने में कोई कमी नहीं**

करतारपुर कॉरिडोर पर जब बातचीत चल रही थी तो भारत के मीडिया को करतारपुर में भारत सीमा के पास आतंकी ट्रेनिंग कैंप नज़र आ रहे थे। सारी ख़बर भारतीय इंटेलीजेंस एजेंसियों के हवाले से आ रही थी। जी न्यूज़, आजतक, एबीपी न्यूज़, रिपब्लिक टीवी, न्यूज़ नेशन, टाइम्स नाउ आदि चैनल चीख चीख कर बता रहे थे कि करतारपुर साहिब के ऐतिहासिक गुरुद्वारे के आसपास मुरिदके, शकरग और नारोवाल में आतंकी ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। उनमें महिलाओं को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। विवादास्पद एंकर दीपक चौरसिया न्यूज नेशन चैनल पर चिल्लाकर इनके तार भारत के हिस्से वाले पंजाब के कुछ संगठनों से जोड़ दे रहा था। उसके सूत्र वही भारतीय इंटेलीजेंस एजेंसियाँ थीं। इन्हीं लाइनों पर सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, रोहित सरदाना, अमीष देवगन, नाविका कुमार, मुंबई खुदकुशी मामले का अभियुक्त अर्नब गोस्वामी की रपटें भी अपने अपने चैनलों पर थीं।

भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियाँ ये ख़बरें यूँ ही नहीं प्लांट कराती हैं। उनका एक पैटर्न होता है। जब किसी तरह का राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा होता है तो इस तरह की ख़बरें प्लांट की जाती हैं। कन्हैया कुमार के दौर में जेएनयू आंदोलन के दौरान उमर ख़ालिद की गुप्त पाकिस्तान यात्रा इन्हीं चैनलों ने कराई थीं और उस ख़बर को इंटेलीजेंस एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से चलाया गया था। जनकवि वरवरा राव, दलित विचारक आनंद तेलतुम्बड़े और आदिवासियों की लड़ाई लड़ने वाली सुधा भारद्वाज को इन्हीं एजेंसियों ने माओवादी बना दिया है। केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल जब कहते हैं कि किसान आंदोलन वामपंथियों और माओवादियों के हाथों में चला गया है तो पूरी सरकार पर बहुत तरस आता है। इतनी लोकप्रिय सरकार चलाने का दावा करने के बाद भी अगर आप से किसान नहीं सँभाले गये और वे भटककर वामपंथियों के खेमे में चले गये तो इसमें किसकी कमी है?

**मोदी का पंजाब**

नब्बे का दशक बीतने वाला था और यही नरेन्द्र मोदी भाजपा में पंजाब के प्रभारी हुआ करते थे। मैं उस समय अमर उजाला के पंजाब मिशन पर था और मेरा मुख्यालय जालंधर था। वहाँ के जाने माने भाजपा नेता मनोरंजन कालिया के आवास पर कई मौक़ों पर मोदी से रूबरू होने का मौक़ा मिलता था। वो वहाँ संगठन मज़बूत करने आये थे। मोदी का उस समय मुझ समेत तमाम पत्रकारों से कहना था कि सिख कभी भी अकालियों और कांग्रेस के क़ब्ज़े से बाहर नहीं आयेंगे, इसलिए हमारी पार्टी का फ़ोकस पंजाब के हिन्दुओं पर मुख्य रूप से है। जालंधर के तमाम मौजूदा वरिष्ठ पत्रकार इन बातों के आज भी गवाह हैं।

पंजाब में आज तक भाजपा सिखों में ऐसा क़द्दावर नेता पैदा नहीं कर सकी है जिसे वह छोटे मोटे मुखौटे के तौर पर पेश कर सके। भारत सरकार आज जिस बुकलेट के ज़रिए मोदी से सिखों के अटूट रिश्तों को जोड़ रही है वह एक छलावा है।

एक जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते मैं आपको असलियत बताता हूँ कि सबसे पहले पंजाब भाजपा के नेताओं ने किसान आंदोलनकारियों को "खालिस्तानी" कह कर प्रचार करना शुरू किया। लेकिन साथ में यह टिप्पणी भी दर्ज करना चाहूँगा कि अगर वाक़ई उन हज़ारों जत्थों में कथित खालिस्तानी, माओवादी घुस आये थे तो क्यों नहीं सेंट्रल एजेंसियों ने ऐसे तत्वों को वहीं गिरफ़्तार किया या पकड़ा? किसानों का कारवाँ तो वहाँ के बाद बढ़ता गया। पंजाब में जब वे थे तो उस समय एक्शन ले लेते।

होता यह है कि सत्ता में होने पर भाजपा के कुछ नेता किसी भी जन आंदोलन को सबसे पहले पाकिस्तानी, खालिस्तानी, माओवादी, अर्बन नक्सली बताकर विवाद खड़ा करते हैं फिर आरएसएस उसे अपने नेटवर्क के ज़रिए जनता में उन बातों को अपने लोगों से कहलवाता है। संघ की शाखा से जुड़े शहरी मध्यम वर्गीय परिवार अपने घरों में, पड़ोसियों से, बाज़ार में, दुकानों पर बेबात उस आंदोलन पर चर्चा शुरू कर देते हैं और अंत में उन्हें पाकिस्तानी, खालिस्तानी या माओवादी क़रार दे देते हैं। किसान आंदोलनकारी अगर जेलों में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, दलित विचारकों, एक्टिविस्टों की रिहाई की माँग कर रहे हैं तो यह अपराध है। इसी अकाली-भाजपाइयों की सरकार ने अपने शासनकाल में कई सजायाफ्ता आतंकियों को रिहा किया तो उसे कोई नाम नहीं दिया गया। यह पहला जन आंदोलन है, जिससे मोदी परेशान हैं। वह ज़मीन से जुड़े नेता हैं और उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि पंजाब का किसान वाक़ई नाराज़ है। चूँकि सिख वहाँ बहुसंख्यक हैं तो इसीलिए सरकार को बताना पड़ रहा है कि मोदी के सिखों से अटूट रिश्ते रहे हैं।

**(यूसुफ किरमानी वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं)**

फैक्ट

# पेट्रोल की क़ीमत के नाम पर आपको बनाया जा रहा है उल्लू

**गिरीश मालवीय**

ये फैक्ट देख लीजिए ये हमारे पड़ोसी देशों में पेट्रोल की कीमतें है, ऐसा नही है कि वहां कोरोना नही है, कोरोना तो वहाँ भी है, आर्थिक परिस्थितियां वहाँ की भी बहुत अच्छी नही है, लेकिन वहाँ की सरकारों ने ऐसी लूट नही मचाई है जैसी मोदी सरकार ने मचा रखी है

आज मोदी सरकार एक लीटर पेट्रोल पर 32.98 रुपये और डीजल पर 31.83 रुपये एक्साइज ड्यूटी ले रही है। जबकि 2014 में केंद्र में मोदी सरकार के आने से पहले मनमोहन सरकार में 1 अप्रैल 2014 को सेन्ट्रल एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर प्रति लीटर मात्र 9.48 रूपए और डीजल पर मात्र 3.56 रूपए ही थी.

2013 में तो क्रूड की कीमतें भी आसमान पर थी लेकिन आज सरकार को मात्र 26 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है लेकिन हम उसकी कीमत 90 रुपये से भी अधिक चुका रहे हैं मई 2014 में मोदी सरकार आने के बाद से अब तक 16 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा चुकी है

आपको याद होगा कि अप्रैल 2017 में मोदी सरकार ने यह फैसला लिया कि अब से रोज ही पेट्रोल-डीजल के दाम तय होंगे।

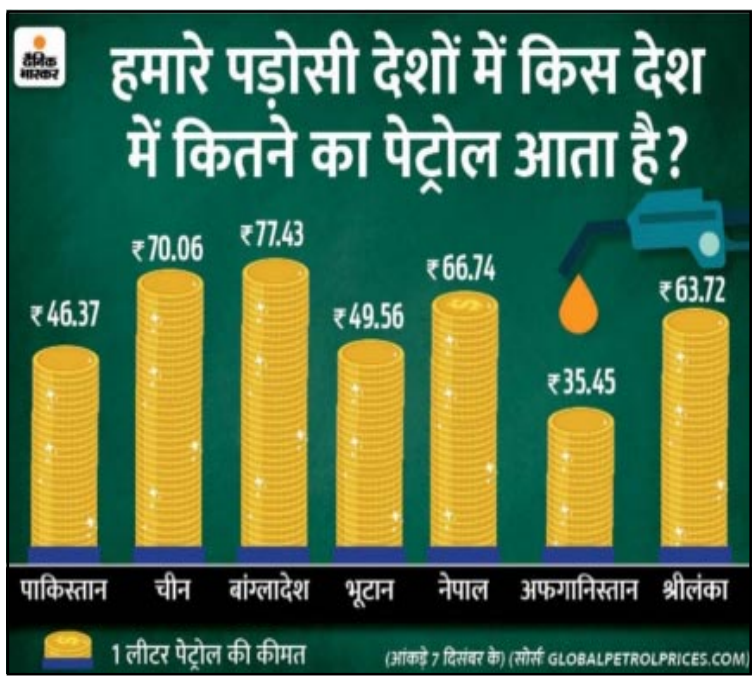


उसके बाद से हर दिन क्रूड की कीमतों से पेट्रोल-डीजल के दाम तय होने लगे। रोज भाव मे घट बढ़ होने लगी उस समय भी यही तर्क दिया गया था कि यदि कच्चे तेल की कीमतें घटी तो फायदा आम आदमी को मिलेगा लेकिन जैसे ही क्रूड की कीमतें कम हुई सरकार में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाना शुरू कर दिया, नतीजा यह हुआ कि कच्चे तेल के दाम गिरने के बाद जितना पेट्रोल-डीज़ल सस्ता होना चाहिए था वो नही हुआ ओर कीमतें लगातार बढ़ती रही.....

आज हालात यह है कि दुनिया मे पेट्रोल डीजल पर भारत में सबसे ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है अमेरिका में पेट्रोल-डीजल पर मात्र 19 प्रतिशत टैक्स लिया जाता है, जबकि इटली में 64 प्रतिशत टैक्स लग रहा है। लेकिन भारत में टैक्स की दर 68 प्रतिशत से भी अधिक हो गयी है, कोरोनाकाल में जब भारत की अधिकांश जनता आर्थिक संकट झेल रही है तब भी उस पर लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों का बोझ लादा जा रहा है।


## घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

**आज ही अपने हॉकर से कहें, कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ़ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें।**

**अन्य बिक्री केन्द्र :**

1. प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड।
2. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन
3. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे।
4. जितेन्द्र, बाटा सेंटर - 9971064207
5. राम खिलावन - बल्लभगढ़ बस स्टैंड के सामने


बेशर्मी की इंतिहा, चपत पर चपत

# डॉ कफील खान के केस में योगी सरकार को फिर लगा धक्का

**ब्यूरो रिपोर्ट**

यूपी की योगी सरकार को डॉ कफ़ील खान के मामले में सुप्रीम कोर्ट से निराशा मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉ कफ़ील खान पर लगाए गए खूँखार यूपीपीए कानून में ज़मानत दे दी थी। इस फ़ैसले के खिलाफ योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। मामले की आज सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसका हाई कोर्ट के फ़ैसले में दखल का कोई इरादा नहीं है। इस पर यूपी सरकार ने कहा कि इस फ़ैसले का डॉ खान पर चल रहे आपराधिक मामले पर असर नहीं पड़ेगा, इसे सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट करे। अदालत ने कहा कि इसमें भी वह कुछ नहीं कहेगा। वो मामला अपनी मेरिट के हिसाब से चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने बहुत शानदार बहस की।

दुःख की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता यूपी सरकार पर किसी तरह का कोई जुर्माना तय नहीं किया। जो बार-बार डा. काफील खान के खिलाफ याचिका लगाती रहती है। अभी तक उनको कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद डॉक्टर कफ़ील ख़ान ने ट्वीट किया, "मेरे इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के ख़िलाफ़ यूपी सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है. अल्लाह शुक्र, जय हिंद जय भारत. बेंच का मानना है कि यह अच्छा फ़ैसला है और इसमें दख़ल देने का कोई कारण नहीं है।"

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1 सितंबर को अपने फ़ैसले में कहा था कि कफ़ील ख़ान को एनएसए के तहत गिरफ़्तार किया जाना "ग़ैर-क़ानूनी" है।

अदालत ने डॉक्टर कफ़ील ख़ान को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया था।

अदालत ने अपने फ़ैसले में कहा था, "डॉक्टर कफ़ील ख़ान का भाषण किसी तरह की नफ़रत या हिंसा को बढ़ावा देने वाला नहीं था, बल्कि यह लोगों के बीच राष्ट्रीय एकता का आह्वान था।"